

[2023] 5 एस. सी. आर 918

प्रवर्तन निर्देश, भारत सरकार

बी.

कपिल वधावन और ए. एन. आर. ईटीसी।

(आपराधिक अपील सं। 701-702 2020 का)

27 मार्च, 2023

[के. एम. जोसेफ, हृषिकेश रॉय और

बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एस. 167 (2) परंतुक (ए) (ii)

डिफॉल्ट जमानत-60/90 दिन की रिमांड अवधि के लिए दावा

-

परंतुक (ए) से एस। 167 (2) - जिस दिन मजिस्ट्रेट रिमांड को शामिल करने या बाहर करने का आदेश देता है, उसकी गणना: एस. 167 (2) एक अभियुक्त को रिमांड पर लेने की मजिस्ट्रेट की शक्ति से संबंधित है और मैगिस्टीरियल कोर्ट की नज़र की तारीख का कोई कारण नहीं है

सुस्त जाँच के कारण हिरासत-निर्धारित 60/90 दिन की रिमांड अवधि। 167 इसकी गणना उस तारीख से की जानी चाहिए जब एक मजिस्ट्रेट रिमांड को अधिकृत करता है-इस प्रकार, जिस क्षण निर्धारित 60/90 दिन की रिमांड अवधि समाप्त हो जाती है, चूक करने का एक अक्षम्य अधिकार है। अभियुक्त को प्राप्त जमानत-तथ्यों के आधार पर अभियुक्तों को 14.05.2020 पर रिमांड पर लिया गया था और इस प्रकार, आरोप पत्र दायर किया जाना चाहिए था।

12.07.2020 पर या उससे पहले (यानी साठवें दिन)-लेकिन वही था

उनकी अभिरक्षा के 61 वें दिन दायर किया गया-इसलिए, अभियुक्त व्यक्तियों को 61 वें दिन 12 बजे डिफॉल्ट जमानत का अधिकार प्राप्त हुआ: 00 एएम,

- ऐसे मामलों में जहां आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट 61 वें/91 वें दिन या उसके बाद दायर की जाती है, आरोपी डिफॉल्ट जमानत का हकदार होगा-इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को डिफॉल्ट जमानत देने में न्यायसंगत ठहराया। एस के परंतुक (ए) (ii) को लागू करके। 167 (2) - धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002। 3 .

एस. 167 (2) रिमांड के दिन को शामिल करके/छोड़कर 60/90 दिन की रिमांड अवधि की गणना के बारे में परस्पर विरोधी राय रुस्तम के मामले ने चंगती के मामले में बाध्यकारी मिसाल को नजरअंदाज कर दिया

918 प्रवर्तन निर्देश, भारत सरकार V. कपिल वधावन और ए. एन. आर., ई. टी. सी.

एस के परंतुक (ए) के तहत निर्धारित 60/90 दिन की अवधि की गणना करना। 167 (2) - इस प्रकार, रुस्तम के मामले में निर्णय असंबद्ध माना गया।

न्यायिक मिसाल का सिद्धांत: इनक्यूरियम के अनुसार-आयोजित नियम: न्यायिक पूर्ववर्ती के सिद्धांत के लिए एक अपवाद है-यह प्रदान करता है

कि जब कोई निर्णय किसी प्रासंगिक पूर्ववर्ती या किसी अन्य बाध्यकारी प्राधिकरण की अज्ञानता में पारित किया जाता है, तो उसे गलत कानून का प्रतिपादन कहा जाता है-अलग-अलग विचारों से उत्पन्न होने वाले संघर्ष को जल्द से जल्द निर्णय के अनुपात का सहारा लेकर हल करना उचित हो जाता है।

सामान्य खंड अधिनियम, 1897: कम्प्यूटिंग के दौरान इसकी प्रयोज्यता

एस के परंतुक (ए) के तहत दिए गए 60/90 दिनों की अवधि। 167 (2) - आयोजित किया गया: सामान्य खंड अधिनियम एस पर लागू नहीं होता है। 167 , जिस अवधि से निर्धारित रिमांड शुरू हो सकती है, उसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है।

संदर्भ का जवाब देते हुए, न्यायालय ने

एक प्रासंगिक पूर्ववर्ती या किसी अन्य बाध्यकारी प्राधिकरण की अज्ञानता में पारित किया गया, इसे गलत कानून का प्रतिपादन कहा जाता है। यह. विचलन से उत्पन्न होने वाले संघर्ष को हल करने के लिए उपयुक्त हो जाता है

सबसे पहले के अनुपात निर्णय का सहारा लेकर राय राय दें। [पैरा 30] [938-डी-ई]

1.2 चगंती के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 167 (2) के परंतुक (ए) में पूर्वनिर्धारित 90/60 दिनों की गणना केवल रिमांड की तारीख से की जा सकती है और यह रिमांड के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है।

संशोधन कि विधायिका ने जांच के उद्देश्य से एक दिन की रिमांड अवधि प्रदान करने का इरादा किया था। यह भी स्पष्ट रूप से राय दी गई थी कि कुल के संदर्भ में परंतुक (ए)

निरोध की अवधि की व्याख्या स्वयं परंतुक की सरल भाषा में की जा सकती है, क्योंकि यह अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और सामान्य खंडों के प्रावधानों को लागू करना पूरी तरह से अनावश्यक है।

अधिनियम या सीमा अधिनियम। एम. पी. बनाम राज्य में रुस्तम के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 167 (2) के परंतुक (ए) में निर्दिष्ट अवधि में रिमांड की तारीख को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। रुस्तम के मामले को पढ़ने पर यह पता चलता है कि अदालत ने अवधि की गिनती करते हुए

सामान्य खंड अधिनियम की धारा 9 और 10 पर विचार किया गया। लेकिन ऐसा करने में, रुस्तम के मामले में अदालत अनुपात [2023] 5 एस. सी. आर. की सराहना करने में विफल रही।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चंगंती के मामले में जहां यह स्पष्ट रूप से देखा गया था कि धारा 167 (2) के तहत अवधि की गणना करने के उद्देश्य से,

सामान्य खंड अधिनियम के प्रावधानों का कोई उपयोग नहीं होगा। धारा 167 (2) के पीछे के विधायी इरादे को ध्यान में रखते हुए, और परंतुक (ए) अपने आप में एक पूर्ण संहिता है, और यह भी स्पष्ट किया गया है

चंगंती के मामले में रुस्तम के मामले में निर्धारित गणना विधि सही तरीका नहीं हो सकता है। इसके अलावा, चूंकि रुस्तम के मामले ने धारा 167 (2) के प्रावधान (ए) के तहत निर्धारित 60/90 दिन की अवधि की गणना करने पर चंगंती के मामले में बाध्यकारी मिसाल को नजरअंदाज कर दिया, जिस तारीख से एक मजिस्ट्रेट ने रिमांड का आदेश दिया था, यह एक प्रति असंवेदनशील निर्णय है। इस प्रकार, गणना की 60/90 दिन की अवधि के संबंध में रुस्तम के मामले में कार्यात्मक भाग, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 9 और 10 को लागू करने के बाद आया, जहां अदालत ने रिमांड की तारीख को बाहर कर दिया और इसके विपरीत को नजरअंदाज कर दिया।

चंगंती के मामले में राय, एक बाध्यकारी न्यायिक मिसाल नहीं हो सकती है जैसा कि इनक्यूरियम के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। [पैरा 26,28,29,31] [937 डी-एफ, जी-एच; 938-ए-सी; 939-बी-सी]

सी. आर. पी. सी., धारा 167 की उप-धारा (1) में निहित प्रावधान उप-धारा (2) की निरंतरता में चलते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी को पेश करना पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी की अगली कड़ी है और साथ ही, आरोपी को भी अपनी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। जिस दिन अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष रिमांड पर लाया जाता है, धारा 167 की उप-धारा (2) मजिस्ट्रेट को या तो उसे जारी रखते हुए या मजिस्ट्रेट हिरासत में भेजकर पुलिस के साथ हिरासत को अधिकृत करने का अधिकार देती है। दोनों प्रक्रियाओं के बीच विराम नहीं हो सकता है। नहीं। परिसीमन की अवधारणा धारा 167 में की गई है और न ही इसे 'और' से 'तक' की सीमा की अवधि में फिट किया जा सकता है क्योंकि जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने की कोई सीमा नहीं है। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की निरंतरता में एक प्रक्रिया है और मजिस्ट्रेट कुल मिलाकर 15 दिनों से अधिक के लिए हिरासत को अधिकृत नहीं करेगा, लेकिन यदि वह संतुष्ट है कि पर्याप्त आधार मौजूद हैं, तो वह पुलिस की हिरासत के अलावा 15 दिनों से अधिक समय के लिए आरोपी की हिरासत को अधिकृत कर सकता है।

उल्लेखनीय है कि ऐसा कोई निश्चित अंतिम बिंदु नहीं है जिसके भीतर पुलिस या जांच अधिकारियों को सूचना निर्देश, भारत सरकार V को पूरा करने की आवश्यकता हो।

कपिल वधावन और ए. एन. आर. ईटीसी।

रिमांड आदेश। यह चंगंती के मामले में निष्कर्ष की व्याख्या करता है कि सामान्य खंड अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 पर लागू नहीं होता है, क्योंकि कोई निश्चित 'से' अवधि नहीं है जिससे निर्धारित रिमांड शुरू हो सकती है। इसके अलावा, तथ्य यह है कि तारीख रिमांड को शामिल किया गया है और निर्धारित अवधि से बाहर नहीं रखा गया है, यह इस महत्वपूर्ण विचार पर आधारित है कि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदेश देती है कि कानून की विशिष्टता में किसी भी कमी की व्याख्या आरोपी के पक्ष में की जानी चाहिए। [पैरा 34] [940 ई-एच; 941-ए-सी] [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.5 धारा 57 सी. आर. पी. सी. आदेश देती है कि अभियुक्त को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर और धारा के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। 167 (2) न्यायिक मजिस्ट्रेट से कार्यकारी कार्रवाई की जांच करने और यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि क्या पुलिस कार्रवाई से अभियुक्तों के अधिकार कम नहीं हुए हैं। का पृथक्करण

कार्यपालिका और न्यायिक शक्ति का प्रयोग अंततः किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है जो अनुच्छेद 21 और 22 (2) के तहत भी संवैधानिक रूप से संरक्षित है। यदि मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित रिमांड की तारीख को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो एक आरोपी हिरासत में होने के बावजूद, उसे दिन की अवधि के भीतर नहीं गिना जाएगा। रिमांड की तारीख पर हिरासत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 56 के तहत एक आरोपी की गिरफ्तारी से अलग है क्योंकि इसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले की अवधि माना जाता है। इस तर्क के अनुसार, भले ही आरोपी हिरासत में हो, यह न तो धारा 56 के तहत होगा और न ही 167 (2) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत। इससे एक स्पष्ट कानूनी रिक्तता पैदा होगी। हालांकि इससे बचा जा सकता है अगर

रिमांड अवधि को रिमांड आदेश के दिन से ही माना जाता है। इसके अलावा, यदि किसी अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा 01.01.2023 कहने पर रिमांड पर लिया जाता है, तो पुलिस, न्यायिक जांच के बाद, उसी दिन से शुरू होकर, धारा 167 सीआरपीसी के अनुसार, जांच करने का अधिकार रखती है, भले ही पुलिस वास्तव में उसी दिन जांच शुरू करे। इसलिए, यदि पुलिस को उस दिन किसी आरोपी व्यक्ति की जांच करने का अधिकार है

रिमांड आदेश स्वयं, 60/90 दिन निर्धारित अवधि, जिसकी समाप्ति पर, अभियुक्त को डिफॉल्ट जमानत का अधिकार प्राप्त होता है, की गणना तार्किक रूप से उसी दिन से की जानी चाहिए। आई. डी. 1 दिन की अवधि में धारा 167 सी. आर. पी. सी. के तहत रिमांड की तारीख को नजरअंदाज करना, सुस्त जांच के कारण आरोपी को लंबे समय तक हिरासत में रहने से सुरक्षा प्रदान करने के विधायी इरादे के खिलाफ होगा। [पैरा 36] [941-ई-जी; 942-ए-सी]

1.6 60/90 दिन की सीमा एक वैधानिक आवश्यकता है जो राज्य की एजेंसियों को उससे आगे के गंभीर अपराधों की जांच करने की अनुमति देती है। 15 दिन की पुलिस हिरासत। यदि राज्य निर्धारित 60/90 के भीतर रिमांड के लिए आरोप पत्र या पूरक अनुरोध दायर करने में विफल रहता है।

दिन की अवधि में, व्यक्ति के अधिकारों और उन अधिकारों पर प्रतिबंध के बीच एक संतुलन बनाया जाना चाहिए और कानूनी सहायता के बिना लंबे समय तक कारावास। उसी उदाहरण में, वैधानिक रिमांड अवधि समाप्त हो जाती है, आरोपी को डिफॉल्ट जमानत का एक अक्षम्य अधिकार प्राप्त होता है और इसे संरक्षित करने की आवश्यकता होती है।

भारत सरकार का प्रवर्तन निर्देश V. कपिल वधावन और ए. एन. आर. ईटीसी।

व्यक्ति की स्वतंत्रता निश्चित रूप से सापेक्ष और विनियमित है। पूर्ण स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जिसकी कल्पना सामाजिक परिवेश में नहीं की जा सकती है। इसलिए कानून अधिकारियों को आरोपी व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अनुमति देता है।

और जांच को सुविधाजनक बनाना। हालाँकि, यह इस अदालत का कर्तव्य है कि वह लंबे समय तक कारावास को हतोत्साहित करे। पूर्वनिर्धारित जमानत का अधिकार

बाद में आरोप पत्र दाखिल करने से समाप्त नहीं होता है, और अभियुक्त को डिफॉल्ट जमानत का अधिकार बना रहता है। [पैरा 42] [944-सी-ई]

1.7 जब रिमांड आदेश का दिन शामिल किया जाता है

धारा 167 (2) के तहत निर्धारित अवधि, अभियोजन पक्ष को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 का तुरंत पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। द.

60 दिनों की अवधि को घटाकर 59 दिनों और कुछ घंटों से अधिक करके अभियुक्त के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की ओर झुकना, एक व्यक्ति को दिए गए संवैधानिक संरक्षण पर आधारित है।

अनुच्छेद 22 (2) और अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त। इस तरह, एक अभियुक्त के साथ व्यवहार करने में संहिता का आवेदन इसके अनुरूप होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का अलंघनीय अधिकार। [पैरा 48] [947 सी-डी]

1.8 चूंकि धारा 167 सी. आर. पी. सी. के अनुप्रयोग और विवरण में रिक्तता मौजूद है, एक व्याख्या जो कारण को आगे बढ़ाती है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का चुनाव किया जाता है। अभियुक्तों को आई. डी. 2 पर रिमांड पर लिया गया था और इस प्रकार, आरोप पत्र आई. डी. 1 (यानी साठवें दिन) को या उससे पहले दायर किया जाना चाहिए था। लेकिन वही दायर किया गया था, केवल 13.07.2020 पर जो उनकी हिरासत का 61 वां दिन था। अतः अभियुक्त व्यक्तियों को व्यतिक्रम जमानत का अधिकार प्राप्त हुआ।

12 बजे 13.07.2020 पर: 00 ए. एम., आधी रात के बाद। उसी दिन, अभियुक्तों ने 8 बजे अपनी डिफॉल्ट जमानत याचिकाएं दायर कीं: 53 एएम।

आरोप-पत्र/अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से पहले जमानत, तो ऐसा अधिकार किसी भी तरह से निराश या समाप्त नहीं होगा बाद में दाखिल करना। धारा 167 सी. आर. पी. सी. के तहत निर्धारित 60/90 दिन की रिमांड अवधि की गणना उस तारीख से की जानी चाहिए जब एक मजिस्ट्रेट रिमांड को अधिकृत करता है। यदि रिमांड के पहले दिन को बाहर रखा जाता है, तो रिमांड की अवधि, अनुमत 60/90 दिनों की अवधि से आगे बढ़ जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप धारा 167 सीआरपीसी के तहत परिकल्पित अवधि से परे अनधिकृत हिरासत होगी।

मामलों में जहाँ [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट 61 वें/91 वें दिन या उसके बाद दायर की जाती है, तो आरोपी डिफॉल्ट जमानत का हकदार होगा। जिस क्षण निर्धारित 60/90 दिन की रिमांड अवधि समाप्त हो जाती है, एक अक्षम्य अभियुक्त को पूर्वनिर्धारित जमानत का अधिकार प्राप्त होता है। [पैरा 50] [947-जी; 948 ए-डी]

1.9 धारा 167 (2) के परंतुक (ए) (ii) को लागू करके प्रत्यर्थियों को डिफॉल्ट जमानत देने वाला उच्च न्यायालय का विवादित आदेश क्रम में पाया गया है। इसलिए, निर्णय पारित किया गया उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश को बरकरार रखा जाता है। [पैरा 51] [948-ई]

एम. पी. बनाम राज्य रुस्तम और ओआरएस। 1995 (सप) 3 एस. सी. सी. 221-प्रति इनक्यूरियम।

चगंती सत्यनारायन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

(1986) 3 एससीसी 141: [1986] 2 एस. सी. आर. 1128-पर निर्भर।

रवि प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य (2015) 8 एस. सी. सी. 340 [2015] 2 एस. सी. आर. 241; एम. रवींद्रन बनाम खुफिया अधिकारी, राजस्व खुफिया निदेशक (2021) 2 एस. सी. सी. 485; सी. बी. आई. बनाम अनुपम जे. कुलकर्णी (1992) 3 एस. सी. सी. 141: [1992] 3 एस. सी. आर. 158; राज्य बनाम मोहम्मद अश्राफ भट (1996) 1 एस. सी. सी. 432: [1995] 6 पूरका एस. सी. आर. 300; राज्य

महाराष्ट्र बनाम भारती चंदमल वर्मा (2002) 2 एस. सी. सी. 121: [2001] 5 पूरका एस. सी. आर. 422; गौतम नवलखा

बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन

एससी 382; असलम बाबालाल देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य (1992) 4 एससीसी 272: [1992] 1 पूरका एस. सी. आर. 545; एन. सुरेया रेड्डी बनाम उड़ीसा राज्य 1985 करोड़ रु. एलजे 939 (ओरी); प्रज्ञा सिंह ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 10 एस. सी. सी. 445: [2011] 14 एस. सी. आर. 617; S.Kasi बनाम राज्य

(2020) एससीसी ऑनलाइन एससी 529; दीपक सत्यवान कुडालकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एम. ए. एन. यू./एम. एच./0843/2020 एल. डी./वी. सी.; राजू उर्फ राज किशोर सिंह बनाम बिहार राज्य (1980) 1 एस. सी. सी. 108; राज कुमार बनाम पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1979 पी. एंड एच. 80; बटना राम बनाम एच. पी. 1980 करोड़ रु. एलजे 748 (एचपी); जगदीश बनाम एम. पी. राज्य 1984 सीआरएल। एलजे 79 (एमपी); ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक (1988) 2 एस. सी. सी. 602 [1988] 1 पूरका एस. सी. आर. 1; शाह फैसल

बनाम भारत संघ (2020) 4 एस. सी. सी. 1: [2020] 3 एस. सी. आर. 1115; संदीप कुमार
बाफना बनाम महाराष्ट्र राज्य 2014

(16) एससीसी 623: [2014] 4 एस. सी. आर. 486; इकोन एंट्री लिमिटेड बनाम।

प्रवर्तन निर्देश, भारत सरकार कपिल वधावन और ए. एन. आर. ईटीसी।

रोम इंडस्ट्रीज (2014) 11 एससीसी 769: [2013] 14 एससीआर

74 ; साकेत इंडिया लिमिटेड बनाम. इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड (1999) 3

एससीसी 1: [1999] 1 एससीआर 963; राकेश कुमार पॉल बनाम.

असम राज्य (2017) 15 एससीसी 67: [2017] 8 एससीआर 785;

भारत संघ बनाम निराला यादव (2014) 9 एस. सी. सी. 457:

[2014] 6 एस. सी. आर. 148; उदय मोहनलाल आचार्य बनाम राज्य

महाराष्ट्र (2001) 5 एस. सी. सी. 453: [2001] 2 एससीआर 878 ; संजय दत्त बनाम। सी. बी. आई. 1994 के माध्यम से बॉम्बे (5)

एस. सी. सी. 410 [1994] 3 पूरक। एससीआर 263; बिक्रमजीत सिंह

बनाम पंजाब राज्य (2020) 10 एससीसी 616; ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ए. आई. आर 1950 एस. सी. 27: [1950] एससीआर 88;

रुस्तम कावासजी कूपर बनाम भारत संघ (1970) 1

एस. सी. सी. 248 [1970] 3 एस. सी. आर. 530; मेनका गांधी बनाम.

भारत संघ ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 597 [1978] 2 एस. सी. आर. 621;

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) 4 एससीसी

225 : [1973] 0 पूरक। एस. सी. आर. 1; ओल्मस्टेड बनाम। अमेरिका, 277 अमेरिका

438 (1928) ; ए. डी. एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976) 2 एससीसी 521: [1976] 0 पूरक। एससीआर 172; के. एस. पुट्टास्वामी

बनाम भारत संघ (2017) 10 एससीसी 1: [2017] 10 एससीआर

569 ; मुन्न वी. इलिनोइस, 94 यू. एस. 113 (1876); खरक सिंह

मुलिन बनाम। प्रशासक, 1981 एआईआर 746-संदर्भित को।

वी. एम. बाचल, इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस,

Vol.25, संख्या 3/4 (जुलाई-सितंबर। दिसंबर, 1964), पीपी। 231-240 ;

जॉन लॉक द्वारा सरकार का दूसरा ग्रंथ

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2015] 2 एससीआर 241

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

(2021) 2 एससीसी 485

पैरा 7

संदर्भित किया गया है

[1986] 2 एससीआर 1128

पैरा 8

संदर्भित किया गया है

[1992] 3 एससीआर 158

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[1995] 6 पूरक। एससीआर 300

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[2001] 5 पूरक। एससीआर 422

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

संदर्भित किया गया है

[1992] 1 पूरक। एससीआर 545

पैरा 17.1 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[20

23]

[2011] 14 एससीआर 617

संदर्भित किया गया है

पैरा

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर. 1979 पी एंड एच 80

पैरा 2

इनक्यूरियम के अनुसार

[1995] (सप) 3 एस. सी. सी. 221

पैरा

[1988] 1 पूरका एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

[2020] 3 एससीआर 1115

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[2014] 4 एससीआर 486

संदर्भित किया गया है

पैरा:

[2013] 14 एससीआर 74

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1999] 1 एससीआर 963

संदर्भित किया गया है

[2017] 8 एससीआर 785

संदर्भित किया गया है

पैरा:

[2014] 6 एससीआर 148

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2001] 2 एससीआर 878

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1994] 3 पूरक। एससीआर 263

संदर्भित किया गया है

पैरा:

(2020) 10 एससीसी 616

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

(2017) 15 एससीसी (109)

संदर्भित किया गया है

पैरा -

[1950] एससीआर 88

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1970] 3 एससीआर 530

संदर्भित किया गया है

पैरा

पैरा

[1978] 2 एससीआर 621

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1973] 0 पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1976] 0 पूरक। एससीआर 172

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2017] 10 एससीआर 569

संदर्भित किया गया है

पैरा

(1964) 1 एससीआर 332

संदर्भित किया गया है

पैरा

पैरा

1981 एयर 746

संदर्भित किया गया है

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: अपराधी।

2020 का Nos.701-702।

एच के 20.08.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

एल. डी. वी. सी. जमानत आवेदन Nos.400 ए 2020 में बॉम्बे में न्यायिक कार्य।

तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, एस. वी. राजू, संजय जैन

मुकेश कुमार मरोरिया, कानू अग्रवाल, राजन कुमार कोरसः

प्रवर्तन निर्देश, भारत सरकार V. कपिल वधावन और ए. एन. आर. ईटीसी।

वेंकटेश, सुश्री साइरिका राजू, अर्काज कुमार, जोहेब हुसैन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

कपिल सिब्बल, मुकल रोहतगी, अमित देसाई, वरिष्ठ अधिवक्ता।, महेश अग्रवाल, अंकुर सहगल, रोहन दक्षिण, शुभम कुलश्रेष्ठ,

कौस्तुभ सिंह, सुश्री कामाक्षी सहगल, सुश्री पूजा कोठारी, सुश्री उर्वी गुप्ते, सुश्री काजल दलाल, सुश्री आकांक्षा सक्सेना, ई. सी. अग्रवाल, श्रीरंग बी. वर्मा, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, भारत

बागला, सुश्री कीर्ति दधीच, सारद कुमार सिंघानिया, अमित के. नैन, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
ऋषिकेश राय, जे।

1. जॉन लॉक ने अपने काम, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट (1689) में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया और कहा कि, "कानून का अंत करना नहीं है।

समाप्त या संयमित करें, लेकिन स्वतंत्रता को संरक्षित और विस्तारित करने के लिए: क्योंकि कानून बनाने में सक्षम सृजित प्राणियों के सभी राज्यों में, जहाँ कोई कानून नहीं है, वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। आई.
2. वर्तमान मामले में, हम ऐसे अभियुक्तों के अधिकारों पर चर्चा करते हैं, जिनकी डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार एक दिन या उससे भी कम के अंतर से शेष राशि में लटक जाता है। जाहिरा तौर पर, कोई इसे महत्वहीन मान सकता है। हालाँकि, इस मामले का संवैधानिक महत्व ऐसा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसे केवल कानून द्वारा स्थापित एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष प्रक्रिया द्वारा छीन लिया जा सकता है, का विश्लेषण और संरक्षण करने की आवश्यकता है। इस मुद्दे को कहना आसान है लेकिन इसका जवाब देना मुश्किल है। यह मामला कानून की भूलभुलैया में अंतर्निहित है कि इस न्यायालय को बातचीत करने की आवश्यकता है। सीधे शब्दों में कहें तो न्यायालय को यह जवाब देने की आवश्यकता है कि क्या धारा के पहले परंतुक के तहत रिमांड की अवधि है। 167 (2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद 'सी. आर. पी. सी. ') में वह दिन शामिल है जिस दिन मजिस्ट्रेट रिमांड का आदेश देता है। परिणाम जो भी हो, यह न्यायालय इस बात से अवगत है कि किसी को भी कानूनी अधिकार के बिना कारावास का सामना नहीं करना चाहिए। हालाँकि, राज्य को अपराध को रोकने और सुरक्षा बनाए रखने का काम सौंपा गया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता-संपार्श्विक नहीं होनी चाहिए।

3. हमने अपीलार्थियों की ओर से भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एस. वी. राजू को सुना है। श्री मुकल रोहतगी, श्री कपिल सिब्बल और श्री अमित देसाई, विद्वान वरिष्ठ वकील उन प्रतिवादियों की ओर से पेश होते हैं जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा डिफ़ॉल्ट जमानत का लाभ दिया गया था।

1 1 जॉन लॉक, 'द सेकंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट', दिसंबर 1689।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. ये अपीलें बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई हैं, जिसमें सीआरपीसी की धारा 167 (2) के परंतुक (ए) (ii) के तहत प्रतिवादियों को डिफॉल्ट जमानत दी गई है। प्रतिवादियों को धारा के तहत अपराध के कथित अपराध के लिए 14.05.2020 पर गिरफ्तार किया गया था।

3 धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'पीएमएलए') और उसी तारीख को रिमांड पर लिया गया था। ई-मेल के माध्यम से 11.07.2020 पर प्रवर्तन निदेशालय (इसके बाद 'ईडी') ने एक याचिका दायर करने का दावा किया।

शिकायत और बाद में 13.7.2020, यानी सोमवार को, इसकी एक भौतिक प्रति अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। इसके लिए आवेदन जमानत का विस्तार 8 बजे 13.07.2020 पर किया गया था: 53 सुबह 11 बजे तक ई-मेल और भौतिक फाइलिंग टोकन के माध्यम से जारी किया जा रहा है।

5. प्रत्यर्थियों द्वारा यह दावा किया गया कि रिमांड की तारीख से 60 दिनों की अवधि यानी 14.5.2020, 12.7.2020 (रविवार) को समाप्त हो गई और अगले दिन, डिफॉल्ट जमानत आवेदन अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए। हालाँकि, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने यह विचार रखते हुए प्रतिवादियों को डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया कि 60 दिन की अवधि 15.5.2020 से शुरू होगी, जिससे रिमांड की तारीख (यानी 14.5.2020) को हटा दिया जाएगा। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के तहत महसूस किया कि 60 दिनों की अवधि की गणना करते समय रिमांड की तारीख को छोड़ना गलत था और यह अभिनिर्धारित किया कि ईडी द्वारा आई. डी. 1 पर आरोप पत्र दाखिल करना, 61 वां दिन होने के कारण, प्रतिवादियों को डिफॉल्ट जमानत का अधिकार होगा। उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय पर इस न्यायालय द्वारा 3.9.2020 पर रोक लगा दी गई थी।

मुद्दे और संदर्भ

6. विचार के लिए जो मुख्य मुद्दा उत्पन्न होता है वह यह है कि रिमांड की तारीख को शामिल किया जाना है या बाहर रखा जाना है, इसके लिए एक दावे पर विचार करने के लिए

डिफॉल्ट जमानत, जब सीआरपीसी की धारा 167 (2) के परंतुक (ए) में अनुध्यात 60/90 दिन की अवधि की गणना की जाती है। इस न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में इस विवादास्पद प्रश्न पर विचार किया गया है, लेकिन इसमें भिन्नता है -

अभियुक्त को प्राप्त डिफॉल्ट जमानत के अधिकार के लिए निर्धारित अवधि की गणना कैसे की जानी है, इस पर राय। कुछ निर्णयों ने रिमांड की तारीख को हटाने का समर्थन किया है, जबकि अन्य निर्णयों में इसके विपरीत विचार लिया गया है।

7. अभियोजन एम. पी. बनाम राज्य में तर्क की रेखा पर निर्भर करता है। रुस्तम & Ors.2, जिसका बाद में रवि प्रकाश सिंह में अनुसरण किया गया बनाम बिहार राज्य 3 और एम. रवींद्रन बनाम खुफिया अधिकारी,

2 1995 (सप) 3 एस. सी. सी. 221

33 (2015) 8 एस. सी. सी. 340 प्रवर्तन निदेशक, भारत सरकार बनाम। कपिल वधावन और ए. एन. आर. ईटीसी। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

राजस्व खुफिया निदेशक, जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि रिमांड की तारीख को निर्धारित 60/90 दिन की अवधि की गणना के लिए बाहर रखा जाना है,

डिफॉल्ट जमानत के अधिकार के लिए, उत्पन्न होना।

8. दूसरी ओर, अभियुक्त अन्य बातों के साथ-साथ चंगती पर भरोसा करते हैं।

सत्यनारायण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 3, सी. बी. आई. बनाम अनुपम जे. कुलकर्णी, 6 राज्य बनाम मोहम्मद। और महाराष्ट्र राज्य बनाम भारती चंदमल वर्मा, 8 ने तर्क दिया कि अभियुक्त की डिफॉल्ट जमानत की पात्रता निर्धारित करने के लिए रिमांड अवधि की गणना करने के लिए रिमांड की पहली तारीख को शामिल किया जाना चाहिए।

9. कानून में उपरोक्त संघर्ष के कारण, एक न्यायिक पहली उत्पन्न हुई है जिसे इस संदर्भ में हल करने की आवश्यकता है। चंगती में

(ऊपर), इस न्यायालय ने वैधानिक रिमांड अवधि के भीतर जांच के समापन के संबंध में विधायी इरादे की जांच करते हुए कहा कि रिमांड आदेश का दिन शामिल किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, एम. रवींद्रन (ऊपर) में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने रवि प्रकाश (ऊपर) पर भरोसा किया, जिसने बदले में रुस्तम (ऊपर) में निर्धारित सिद्धांत का पालन किया और घोषणा की कि अभियुक्त के डिफॉल्ट जमानत के अधिकार को सुविधाजनक बनाने के लिए अनिवार्य 60/90 दिन की अवधि की गणना के लिए रिमांड की तारीख को बाहर रखा जाना है।

10. चंगती में घोषित कानून की पिछली स्थिति को रुस्तम में नजरअंदाज कर दिया गया था। और चूंकि, रुस्तम बाद में बहिष्कृत करने का आधार बन गया

रवि प्रकाश के मामले में निर्धारित अवधि से रिमांड की तारीख और उसके बाद रवींद्रन के मामले में, जो कि 3-न्यायाधीशों की पीठ का नवीनतम निर्णय है, उचित संख्या वाली पीठ के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह इस मामले में कानून का निपटारा करे। पहले के उदाहरणों और उनमें भ्रम को नोट करें। जब तक इस मुद्दे का समाधान नहीं किया जाता है, तब तक इस बात पर मतभेद होगा कि डिफॉल्ट जमानत के अधिकार, जो अंततः एक मौलिक अधिकार है, की रक्षा कैसे की जानी चाहिए।

11. इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ, 23.2.2021 पर, 60/90 दिन की रिमांड अवधि की गणना पर कानून के विचलन को ध्यान में रखते हुए

सी. आर. पी. सी. की धारा 167 (2) के परंतुक (ए) ने इस मुद्दे को इस तीन-न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया। यहाँ दिए गए उत्तर से डिफॉल्ट जमानत के अधिकार के मुद्दे पर कानून के एक समान अनुप्रयोग की सुविधा होगी। संदर्भ का उत्तर इस प्रकार दिया जा रहा है:

(2021) 2 एससीसी 485

5 (1986) 3 एससीसी 141

6 (1992) 3 एससीसी 141

7 (1996) 1 एस. सी. सी. 432 8 (2002) 2 एस. सी. सी. 121 9 गौतम नवलखा
बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 382 [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वास्तविक पृष्ठभूमि

12. दोनों उत्तरदाता, सी. बी. आई. द्वारा पंजीकृत आर. सी. No.219/2020 में 10.5.2020 के बाद से न्यायिक हिरासत में बंद हैं।

पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध के कथित अपराध के लिए ईडी द्वारा पंजीकृत ईसीआईआर/एमबीजेडओ-1/3/2020 में आरोपी के रूप में आरोपित। 14.5.2020 पर, आवेदकों को विशेष अदालत, मुंबई के समक्ष पेश किया गया और फिर उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया और 27.5.2020 पर बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उच्च न्यायालय ने आवेदकों को डिफॉल्ट जमानत देते हुए निर्णय के लिए निम्नलिखित प्रश्न तैयार किया:

" चाहे सी. आर. पी. सी. की धारा 167 (2) के परंतुक (ए) में विचार के अनुसार 60 या 90 दिनों की रिमांड अवधि की गणना में,

रिमांड के दिन को शामिल या बाहर रखा जाना है।

13. आवेदकों ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि उन्हें 14.5.2020 पर गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन उन्हें गिरफ्तार किया गया था

मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड पर लिया जाता था और इस तरह के रिमांड आदेश समय-समय पर पारित किए जाते थे। ईडी के अनुसार, आई. डी. 1 (यानी एक शनिवार) को, उनके द्वारा ई-मेल के माध्यम से एक शिकायत दर्ज की गई थी और आवेदकों द्वारा यह तर्क दिया गया था कि यह केवल एक अग्रिम था लेकिन पूरी शिकायत नहीं थी। 13.7.2020 यानी सोमवार को, ईडी ने अदालत के समक्ष भौतिक शिकायत दर्ज की। इन तथ्यों के आधार पर, आवेदकों के वकील ने प्रस्तुत किया कि आवेदकों (14.5.2020) की रिमांड की तारीख से 60 दिनों की अवधि 12.7.2020 (रविवार) को समाप्त हो गई और 13.7.2020 पर आवेदकों ने धारा 167 (2), दंड प्रक्रिया संहिता के परंतुक (ए) (ii) के तहत डिफॉल्ट जमानत पर विस्तार की मांग की। प्रारंभ में, आवेदन लगभग 8 बजे ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किए गए थे: 53 सुबह और लगभग दो घंटे बाद, लगभग 11 बजे, जमानत आवेदनों को सत्र न्यायालय में भौतिक रूप से दाखिल करने के लिए प्रस्तुत किया गया

और फाइलिंग को स्वीकार करने वाला एक टोकन जारी किया गया था और आवेदनों को भी क्रमांकित किया गया था।

14. ईडी ने ई-मेल के माध्यम से शिकायत दर्ज करने का दावा किया है।

11.7.2020 इसके बाद 13.7.2020 पर एक भौतिक आवेदन। ईडी के अनुसार, रुस्तम (उपरोक्त) पर भरोसा करते हुए, 60 दिनों की अवधि 13.7.2020 पर समाप्त होती है (जिसमें यह रिमांड की तारीख यानी 14.5.2020 को बाहर करना चाहता है)। इस प्रकार, ईडी के अनुसार, समय पर शिकायत दर्ज की गई।

15. विद्वान विशेष न्यायालय ने 14.7.2020 पर डिफ़ॉल्ट जमानत को इस समझ के साथ अस्वीकार कर दिया कि शिकायत दर्ज करने के लिए 60 दिनों की समय सीमा समाप्त हो गई है। विद्वान न्यायाधीश ने राय दी कि रिमांड की तारीख को निर्देश, भारत सरकार V को लागू करना होगा।

कपिल वधावन और ए. एन. आर. ईटीसी। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

इसे हटा दिया जाएगा और 60 दिनों की अवधि की गणना 15 मई 2020 से करनी होगी। इसी तर्क के साथ जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

16. उनके डिफॉल्ट जमानत आवेदनों की अस्वीकृति के लिए उत्तरदाताओं की चुनौती पर, उच्च न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी के निहितार्थ का विश्लेषण करने के बाद

प्रस्तुतियाँ और वैधानिक प्रावधानों और मामले के तथ्यों के लिए उनके आवेदनों की व्याख्या करते हुए, यह निष्कर्ष निकाला गया कि विद्वान विशेष न्यायाधीश ने 60 दिन की अवधि की गणना करते हुए रिमांड की तारीख को गलत तरीके से बाहर कर दिया। चूंकि ईडी द्वारा आरोप पत्र 13.7.2020 पर दायर किया गया था, इसलिए रिमांड के दिन यानी 14.5.2020 को शामिल करके 60 दिनों से अधिक होने के कारण, आवेदक डिफॉल्ट जमानत के हकदार पाए गए। तदनुसार, अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अपने जमानत बांड प्रस्तुत करने के अधीन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के प्रावधानों को स्वीकार करते हुए प्रतिवादियों की रिहाई के लिए एक निर्देश जारी किया गया था। उच्च न्यायालय के इस आदेश को वर्तमान में चुनौती दी गई है।

अपीलें करें।

परिषद की सामग्री

17.1 दिनांकित 20.8.2020 के निर्णय की वैधता का दावा करते हुए, श्री एस. वी. राजू, विद्वान ए. एस. जी, का तर्क है कि निर्धारित की गणना के लिए

60/90 दिन रिमांड अवधि, रिमांड अवधि के दोनों ओर के दिनों में से एक को बाहर रखा जाना चाहिए और वर्तमान मामले में, या तो रिमांड की तारीख यानी 14.5.2020 या 60 वें दिन यानी 12.07.2020 को डिफॉल्ट जमानत के लिए पात्रता की गणना के लिए बाहर रखा जाना चाहिए। ईडी की दलीलों के समर्थन में, श्री राजू, अन्य बातों के साथ-साथ, असलम बाबालाल देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य, मध्य प्रदेश राज्य बनाम रुस्तम पर मजबूत निर्भरता रखेंगे।

(ऊपर) और रवि प्रकाश सिंह उर्फ अरविंद सिंह बनाम बिहार राज्य (ऊपर)।

17.2 एक वैकल्पिक तर्क भी इस प्रभाव के लिए बनाया गया है कि भले ही

धारा 167 के पहले परंतुक के तहत निर्धारित 60 दिनों की अवधि (2) सी. आर. पी. सी. की अवधि 12.7.2020 को समाप्त हो गई, वही रविवार होने के कारण, धारा 10, सामान्य खंड अधिनियम के प्रावधान लागू हो जाएंगे और इस तरह रविवार को समाप्त होने वाली 60 दिनों की अवधि सोमवार यानी 13.7.2020 तक बढ़ा दी जाएगी। इस तरह के विवाद के समर्थन में, श्री राजू ने एन. सुरेया रेड्डी बनाम उड़ीसा राज्य पर भरोसा रखा।

17.3 . विद्वान ए. एस. जी. ने यह भी तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने धारा 167 (2) के पहले परंतुक के तहत डिफॉल्ट जमानत की अवधि की गणना करने के लिए चगंती (उपरोक्त) में अनुपात पर गलत तरीके से भरोसा किया था।

10 (1992) 4 एससीसी 272।

11 1985 सीआरएल। एलजे 939 (ओरी)

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सीआरपीसी। चूंकि गिरफ्तारी की तारीख रिमांड की तारीख के समान है, इसलिए विद्वान ए. एस. जी. के अनुसार चंगंती (ऊपर) में अनुपात का कोई आवेदन नहीं है और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान तथ्यों में गलत तरीके से लागू किया गया था।

18.1 इसके विपरीत, श्री मुकल रोहतगी, श्री कपिल सिब्बल और श्री अमित देसाई, उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ वकीलों का तर्क है कि अवधि

सी. आर. पी. सी. की धारा 167 (2) के परन्तुक (ए) के तहत परिकल्पित की गई गणना रिमांड आदेश की तारीख से की जानी चाहिए और अभियुक्त पर न्यायालय की नज़र के पहले दिन का बहिष्कार अतार्किक होगा। वकील ने अपनी दलीलें चंगंती (ऊपर) में अनुपात पर आधारित की हैं जिसे बाद के कई फैसलों जैसे कि सीबीआई विशेष जांच प्रकोष्ठ, नई दिल्ली बनाम अनुपमा कुलकर्णी (ऊपर), प्रज्ञा सिंह ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य में अनुमोदित किया गया था। के लिए सलाहकार

उत्तरदाता राज्य बनाम मोहम्मद अशरफ भट (ऊपर), S.Kasi बनाम राज्य 1 3, और गौतम नवलखा बनाम एन. आई. ए. (ऊपर) के निर्णयों पर भी भरोसा करते हैं।

चर्चा

19. विवादित फैसले में बंबई उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने मंजूरी के साथ एक समन्वय पीठ के फैसले का हवाला दिया था

दीपक सत्यवान कुडालकर बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1 4 14 में जहां चूक जमानत के लिए लागू उच्चतम न्यायालय के सभी पिछले निर्णयों पर विचार और विश्लेषण किया गया था। हम प्रकाश डी. नाइक जे. द्वारा लिखी गई राय से लाभान्वित हो सकते हैं, जिन्होंने निम्नलिखित पैराग्राफ में सीआरपीसी के लागू प्रावधानों का विश्लेषण किया था।

‘ 7. उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन पर (सेक. 167 सी. आर. पी. सी.), यह देखा जा सकता है कि उप-धारा (1) अनिवार्य प्रावधान है, जो यह नियंत्रित करता है कि एक पुलिस अधिकारी को क्या करना चाहिए, जब व्यक्ति

गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में रखा जाता है और जब यह प्रतीत होता है कि

धारा 57 द्वारा निर्धारित चौबीस घंटे की अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं की जा सकती है। उप-धारा (2) मजिस्ट्रेट के लिए उपलब्ध रिमांड की शक्तियों और उस तरीके से संबंधित है जिसमें ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। धारा 167 की उप-धारा (1) की अवधि को धारा 57 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि धारा 57

एक पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने से रोकता है

बिना वारंट के लंबी अवधि के लिए फिर चौबीस घंटे

1 2 12 (2011) 10 एससीसी 445 13 (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी.
529 14 एम. ए. एन. यू./एम. एच./0843 2020; एल. डी./वी. सी. आपराधिक जमानत आवेदन
197/2020।

ORCEMENT DIRECTORATE, भारत सरकार v. ए. पी. आई. एल. वधावन और ए. एन. आर. ईटीसी। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए बिना, के अधीन

इस बात का अपवाद है कि गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट न्यायालय तक की यात्रा करने के लिए लिए गए समय को चौबीस घंटे की निर्धारित अवधि से बाहर रखा जा सकता है। चूंकि, उप-धारा (1) में प्रावधान है कि यदि धारा 57 द्वारा निर्धारित चौबीस घंटे की अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं की जा सकती है, तो आरोपी को डायरी में प्रविष्टियों के साथ मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना चाहिए, यह इस प्रकार है कि एक पुलिस अधिकारी जांच के उद्देश्यों के लिए एक गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम चौबीस घंटे की अवधि के लिए हिरासत में रखने का हकदार है। अतः, गिरफ्तार व्यक्ति की अभिरक्षा की प्रारंभिक अवधि, जब तक कि उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया जाता है, न तो मजिस्ट्रेट द्वारा पारित रिमांड के आदेश के लिए संदर्भित है और न ही उसके अनुसरण में है। मजिस्ट्रेट को दी गई रिमांड की शक्तियों का उपयोग धारा 167 की उप-धारा (1) के संदर्भ में किसी आरोपी को उसके सामने पेश करने के बाद किया जा सकता है। धारा 167 की उप धारा (1) में इस प्रक्रिया को शामिल किया गया है और यह भी कहा गया है कि पुलिस अधिकारी को आरोपी को निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजते समय मामले से संबंधित डायरी में प्रविष्टियों की एक प्रति भी प्रेषित करनी चाहिए। डायरी में प्रविष्टियाँ मजिस्ट्रेट को आवश्यक जानकारी देने के लिए होती हैं, जिसके आधार पर वह निर्णय ले सकता है कि आरोपी को हिरासत में रखा जाना चाहिए या नहीं। कानून कहता है

जाँच एजेंसी को जाँच करने के लिए, एक ऐसे मामले में जहाँ एक व्यक्ति को गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया है,

अत्यंत तात्कालिकता के साथ और निर्धारित अवधि में जांच को तुरंत पूरा करें। उप-धारा (2) का परंतुक बाहरी सीमा निर्धारित करता है जिसके भीतर जांच पूरी की जानी चाहिए और यदि निर्धारित अवधि के भीतर इसे पूरा नहीं किया जाता है, तो अभियुक्त जमानत पर रिहा होने का अधिकार प्राप्त करेगा और यदि वह जमानत देने के लिए तैयार है और करता है, तो मजिस्ट्रेट

उसे जमानत पर रिहा करेगा और ऐसी रिहाई को Cr.P.C के अध्याय XXXIII के तहत जमानत का अनुदान माना जाएगा। 1978 के अधिनियम संख्या 45 द्वारा जोड़ा गया परंतुक तब लागू होता है जब मजिस्ट्रेट उचित समझता है कि पंद्रह दिनों की अवधि से आगे हिरासत आवश्यक है और यह निर्धारित करता है कि मजिस्ट्रेट 15 दिनों की अवधि से अधिक पुलिस की हिरासत में रहने के अलावा आरोपी व्यक्ति को हिरासत में रखने के लिए अधिकृत कर सकता है।

दिन होते हैं। धारा 167 (2) के परंतुक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुल [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निरोध की अवधि उन मामलों में नब्बे दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए जहां जांच उसमें उल्लिखित गंभीर अपराधों से संबंधित है और अन्य मामलों में साठ दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए और यदि उस समय तक उक्त अवधि की समाप्ति पर आरोप पत्र दायर नहीं किया जाता है तो आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।

20. विवादित फैसले में उल्लिखित उदाहरण और दीपक सत्यवान (ऊपर) में समन्वय पीठ से पता चलता है कि न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को किसी संदिग्ध को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करता है और संहिता के तहत विचार की गई जांच में सभी कदम शामिल होंगे जिनमें शामिल हैं -

साक्ष्य के संग्रह के लिए कार्यवाही और जांच के समापन पर धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

सीआरपीसी। बारहवें अध्याय का उद्देश्य यह है कि जाँच बिना अनावश्यक देरी के पूरी की जानी चाहिए, हालाँकि जाँच को पूरा करने के लिए कोई स्पष्ट बाहरी सीमा नहीं है। सी. आर. पी. सी. धारा 173 (2) के तहत, अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए निर्धारित करता है, जो न्यायालय को किसी अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार देता है। यह आगे की जाँच के लिए भी अनुमति देता है

धारा 173 की धारा (8)। इसके अलावा, धारा 173 (4) के अनुसार, अंतिम रिपोर्ट दायर होने पर, यदि किसी आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा उसके जमानत बांड को रद्द किया जा सकता है।

जांच पड़ताल की। इस प्रकार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के परन्तुक (ए) के बदले किसी अभियुक्त को दिया गया संरक्षण केवल निर्धारित दिन की अवधि के संबंध में है, जिसके बाद किसी अभियुक्त की अभिरक्षा की मांग नहीं की जा सकती है, भले ही जांच अधूरी हो।

21. जब तक सी. आर. पी. सी. की धारा 167 के तहत मजिस्ट्रेट से विशेष आदेश प्राप्त नहीं किया जाता है, तब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सी. आर. पी. सी. की धारा 57 के तहत निर्धारित 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को हालांकि बाहर रखा जा सकता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट के प्राधिकरण से पहले पुलिस को किसी आरोपी को अपनी हिरासत में रखने के लिए 24 घंटे की अनुमति दी गई है, जैसा कि धारा 167 सीआरपीसी के तहत अनिवार्य है।

22. आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद और पुलिस पूरा करने में असमर्थ है

अनिवार्य 24 घंटे की अवधि के भीतर जाँच करने वाला पुलिस अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत अभियुक्त को मजिस्ट्रेट को प्रेषित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। धारा की उप-धारा (2)

167 फिर मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली कार्रवाई निर्धारित करता है जिसके पास आरोपी व्यक्ति को भेजा जाता है और मजिस्ट्रेट तब आरोपी को हिरासत में रखने के लिए आगे की हिरासत के लिए अधिकृत कर सकता है। उप-धारा (2) के संदर्भ में, मजिस्ट्रेट ऐसी अभिरक्षा में अभियुक्त को हिरासत में रखने के लिए भारत सरकार को प्राधिकृत कर सकता है।

कपिल वधावन और ए. एन. आर. ईटीसी। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

जैसा कि वह कुल मिलाकर 15 दिनों से अधिक की अवधि के लिए उचित समझता है, लेकिन यदि उसके पास मामले का परीक्षण करने या इसे परीक्षण के लिए प्रतिबद्ध करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और विचार करता है कि हिरासत अनावश्यक है, डायरी में प्रविष्टियों के अवलोकन पर, वह आरोपी को रिहा कर सकता है या उसे मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है

उचित क्षेत्राधिकार। उप-धारा को एक परंतुक के साथ जोड़ा गया है जो मजिस्ट्रेट की शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है और अधिकृत करता है अभियुक्त व्यक्ति को पुलिस की अभिरक्षा के अलावा 15 दिनों की अवधि से अधिक समय तक हिरासत में रखना, यदि उसकी राय है कि परिस्थितियाँ ऐसी माँग करती हैं। लेकिन, मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त व्यक्ति को 90 या 60 दिनों से अधिक की कुल अवधि के लिए हिरासत में रखने के लिए अधिकृत नहीं करेगा।

परंतुक (क) का खंड (i) या खंड (ii) क्रमशः। यदि निर्धारित अवधि के भीतर जाँच पूरी नहीं की जाती है तो अभियुक्त को अधिकार प्राप्त होता है।

उसकी रिहाई। 23. जैसा कि उपरोक्त से देखा जा सकता है, अभियुक्त की 24 घंटे से अधिक की हिरासत मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकरण के अधीन है और

अभियुक्त के निरोध को प्राधिकृत करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति

यदि अभियोजन पक्ष आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रहता है, तो अभियुक्त व्यक्ति को डिफॉल्ट जमानत पर रिहा होने का अक्षम्य अधिकार है। 24. दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 में मूल रूप से अधिनियमित धारा 167 में 24 घंटे के भीतर जांच पूरी करने की परिकल्पना की गई है। लेकिन, सीमित समय के भीतर जांच पूरी करने में कठिनाई को देखते हुए, विशेष रूप से जटिल अपराधों के लिए, भारत के विधि आयोग ने

जांच पूरी करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की सिफारिश की गई। 41 वें विधि आयोग की रिपोर्ट (सितंबर, 1969) की सिफारिश के आधार पर, दंड प्रक्रिया संहिता को 1978 के अधिनियम 45 के माध्यम से संशोधित किया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 में खंड (i) और (ii) वाले प्रावधान (ए) को जोड़ा गया था। इस तरह के समावेश के साथ, जबकि जांच अभी भी अपेक्षित है शीघ्रता से पूरा करने के लिए, यह अतिरिक्त प्रावधान किया गया था कि केवल मजिस्ट्रेट के प्राधिकरण के साथ, परंतुक (ए) के तहत खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट अवधि के लिए आगे हिरासत की अनुमति है।

मजिस्ट्रेट [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हालाँकि, हिरासत को अधिकृत करने के लिए विस्तार के अपने कारणों को दर्ज करना होगा।

धारा 167 की उप-धारा (3) के तहत किसी आरोपी को हिरासत में लेना। धारा 167 (2) के पहले परंतुक का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों पर निर्धारित अवधि के भीतर तेजी से जांच पूरी करने और ढिलाई को रोकने के लिए दबाव डालना है। डिफॉल्ट रूप से, मजिस्ट्रेट अभियुक्त को रिहा कर देगा जमानत। यह धारा 436-ए में लगाए गए प्रतिबंध के अधीन है, जिसमें अधिकतम अवधि के लिए प्रावधान किया गया है, जिसके लिए एक विचाराधीन कैदी हो सकता है

हिरासत में लिया गया। अध्याय XXXVI कुछ अपराधों में संज्ञान लेने के लिए सीमा का प्रावधान करता है। धारा 468 का संज्ञान लेने पर रोक लगाती है

सीमा की अवधि, जिस दिन से ऐसी अवधि की गणना की जानी है, को बाहर रखा जाएगा। धारा 468 और धारा 436 ए में निहित उक्त प्रावधान को छोड़कर, जांच पूरी करने में कोई सीमा निर्धारित नहीं है और जांच धारा 167 की उप-धारा (2) के पहले परंतुक के संदर्भ में 60 वें या 90 वें दिन की समाप्ति पर आरोपी को प्राप्त होने वाले डिफॉल्ट जमानत अधिकार को छोड़कर जारी रह सकती है। इस प्रकार, 60/90 दिन की वैधानिक अवधि के लिए प्रावधान करने वाला विधायी इरादा-एक दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है, पहला अभियुक्त का त्वरित मुकदमा जो बदल जाएगा। उसे एक दोषी के रूप में या मुकदमे की समाप्ति पर उसकी रिहाई और दूसरा, पीड़ित और सामान्य रूप से समाज को त्वरित न्याय का आश्वासन देना।

25. संहिता की धारा 167 (2) में परंतुक (ए) को शामिल करने की जांच और विश्लेषण चगंती (उपरोक्त) में किया गया था। लिखित रूप में दोनों-न्यायाधीश

इस मामले में न्यायपीठ की राय में, न्यायाधीश एस. नटराजन को राजू उर्फ राज किशोर सिंह बनाम बिहार राज्य 1 5 में तर्क और अनुपात की जांच करने का अवसर मिला और साथ ही राज कुमार बनाम पंजाब राज्य 1, बटना राम बनाम राज्य 1, जगदीश बनाम राज्य 2 और एन. सुरेया रेड्डी बनाम ओडिशा राज्य (उपरोक्त) में उच्च न्यायालय के फैसलों की भी जांच करने का अवसर मिला और विद्वान न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

" 31. दोनों पक्षों द्वारा उद्धृत कुछ निर्णय 1978 के अधिनियम 45 द्वारा परंतुक (ए) के संशोधन से पहले दिए गए हैं और कुछ संशोधन के बाद दिए गए हैं। श्री.

15 (1980) 1 एससीसी 108 16 एयर 1979 पी एंड एच 80 17 1980
सीआरएल। एलजे 748 (एचपी) 18 1984 करोड़। एलजे 79 (एमपी)

प्रवर्तन निर्देश, भारत सरकार V. कपिल वधावन और ए. एन. आर. ईटीसी। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

राम रेड्डी ने यह तर्क देते हुए पहले के फैसलों में अंतर करने की कोशिश की कि परंतुक (ए) में संशोधन के कारण उनकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, जिससे यह अपने आप में एक स्वतंत्र अनुच्छेद बन गया है। चूंकि, हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी भी तरह से परंतुक (ए) का अर्थ धारा 167 (2) के संदर्भ में या उसके संदर्भ के बिना विधानमंडल द्वारा निर्धारित 90 दिनों और 60 दिनों की अवधि को केवल रिमांड की तारीख से ही गिना जा सकता है, जो 1978 के संशोधन अधिनियम 45 से पहले दिए गए निर्णयों और उसके बाद के बीच किए जाने वाले अंतर का अधिक महत्व नहीं है।

32. चूंकि निरोध की कुल अवधि के संदर्भ में परंतुक (क) की शर्तों की व्याख्या परंतुक की सरल भाषा में की जा सकती है, इसलिए हम नहीं समझते कि परंतुक की शर्तों का अर्थ निकालने के लिए सामान्य खंड अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना या सीमा अधिनियम से मार्गदर्शन लेना आवश्यक है।

26. हालांकि, यह देखते हुए कि कुछ पूर्व उल्लिखित निर्णय 1978 के संशोधन अधिनियम 45 द्वारा परंतुक (ए) को शामिल करने से पहले थे, चंगंती (उपरोक्त) में यह राय दी गई थी कि उन पहले के मामले कानूनों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। अदालत ने तब कहा कि धारा 167 (2) के परंतुक (ए) में पूर्वनिर्धारित 90/60 दिनों की गणना केवल रिमांड की तारीख से की जा सकती है और संशोधन के माध्यम से यह स्पष्ट किया जाता है कि विधायिका ने जांच के उद्देश्य से 90/60 दिन की रिमांड अवधि प्रदान करने का इरादा किया था। यह भी स्पष्ट रूप से राय दी गई थी कि निरोध की कुल अवधि के संदर्भ में परंतुक (ए) की व्याख्या परंतुक की ही सरल भाषा में की जा सकती है, क्योंकि यह अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और सामान्य खंड अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना पूरी तरह से अनावश्यक है या सीमा अधिनियम।

27. चंगंती (ऊपर) में उपरोक्त आधिकारिक घोषणा

बाद में गौतम नवलखा (उपरोक्त) में विचार किया गया, जिसमें निर्धारित 60/90 दिन की रिमांड अवधि की गणना के लिए रिमांड की तारीख शामिल की गई थी।

28. उपरोक्त संदर्भ में, आइए अब हम एम. पी. बनाम राज्य के निर्णय की जांच करें। रुस्तम (ऊपर), और रवि प्रकाश सिंह बनाम स्टेट ऑफ

बिहार (ऊपर) जिन पर विद्वान ए. एस. जी. का तर्क है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के परंतुक (ए) में निर्दिष्ट अवधि में रिमांड की तारीख को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। रुस्तम (ऊपर) पढ़ने पर, यह आता है

इस बात पर प्रकाश डालें कि न्यायालय ने अवधि की गिनती करते समय धारा 9 [2023] 5 एस. सी. आर. पर विचार किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और सामान्य खंड अधिनियम के 10. लेकिन ऐसा करने में, रुस्तम (ऊपर) में न्यायालय चंगती (ऊपर) में अनुपात की सराहना करने में विफल रहा, जहां यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि धारा 167 (2) के तहत अवधि की गणना करने के उद्देश्य से, सामान्य खंड अधिनियम के प्रावधानों का कोई उपयोग नहीं होगा। जहाँ तक रवि प्रकाश सिंह (ऊपर) का उल्लेख है

29. धारा 167 (2) सी. आर. पी. सी. के पीछे के विधायी इरादे को ध्यान में रखते हुए, और परंतुक (ए) अपने आप में एक पूर्ण संहिता है, जैसा कि इसमें भी स्पष्ट किया गया है। चंगती (सुप्रा), रुस्तम (सुप्रा) में निर्धारित गणना विधि, सही तरीका नहीं हो सकता है। इसके अलावा, चूंकि रुस्तम (ऊपर) ने धारा 167 (2) के परंतुक (ए) के तहत निर्धारित 60/90 दिन की अवधि की गणना करने पर चंगती (ऊपर) में बाध्यकारी पूर्ववर्ती को नजरअंदाज कर दिया, जिस तारीख से एक मजिस्ट्रेट ने रिमांड का आदेश दिया, यह एक प्रति अभेद्य निर्णय है।

30. बाध्यकारी पूर्ववर्ती का कानून प्रदान करता है कि प्रति इनक्यूरियम का नियम न्यायिक पूर्ववर्ती के सिद्धांत के लिए एक अपवाद है। काफी हद तक

शाब्दिक रूप से, यह प्रावधान करता है कि जब कोई निर्णय किसी प्रासंगिक पूर्ववर्ती या किसी अन्य बाध्यकारी प्राधिकरण की अज्ञानता में पारित किया जाता है, तो उसे गलत कानून का प्रतिपादन कहा जाता है। प्रारंभिक राय के अनुपात निर्णय का सहारा लेकर अलग-अलग विचारों से उत्पन्न होने वाले संघर्ष को हल करना उचित हो जाता है। इस संदर्भ में न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया, ए. आर. अंतुले बनाम 7 न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय में। आर. एस. नायक [(1988) 2 एस. सी. सी. 602] ने कहा कि:

" मुद्दा यह है कि जिस परिस्थिति में निर्णय लिया जाता है

प्रति इनक्यूरियम केवल इसके निर्णय को अस्वीकार करने का काम करता है

पूर्ववर्ती मूल्य।

इस तरह का निर्णय न्यायिक मिसाल के रूप में बाध्यकारी नहीं होगा।

यह। एक बड़ी पीठ इस तरह के निर्णय को रद्द कर सकती है। " इसी तरह, शाह फैसल बनाम संघ के मामले में एक संविधान पीठ

भारत 20 ने संदीप कुमार बाफना बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में इस न्यायालय के फैसले पर ध्यान देते हुए 21 ने विशेष रूप से कहा:

19 ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक (1988) 2 एस. सी. सी. 602, पैरा 183 (प्रति एम. एन. वेंकटचलैया जे.) 20 शाह फैसल बनाम भारत संघ, (2020) 4 एस. सी. सी. 1 (पैरा 33)

21 2014 (16) एस. सी. सी. 623 प्रवर्तन निर्देश, भारत सरकार v. कपिल वधावन और ए. एन. आर. ईटीसी। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

..... कोई निर्णय या निर्णय आकस्मिकता के अनुसार भी हो सकता है यदि किसी सह-समान या बड़ी पीठ के पहले घोषित निर्णय के साथ इसके अनुपात का मिलान करना संभव नहीं है या यदि उच्च न्यायालय का निर्णय इस अदालत के विचारों के अनुरूप नहीं है।

31. यह ऊपर से तार्किक रूप से प्रवाहित होता है कि गणना की दिन की अवधि के संबंध में रुस्तम (सुप्रा) में कार्यात्मक भाग, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 9 और 10 को लागू करने के बाद आया, जिसमें अदालत ने रिमांड की तारीख को बाहर रखा और चंगंती (सुप्रा) में विपरीत राय को नजरअंदाज कर दिया, एक बाध्यकारी न्यायिक उदाहरण नहीं हो सकता है क्योंकि इसे प्रति इनक्यूरियम प्रस्तुत किया जाता है।

32. महत्वपूर्ण रूप से राज्य बनाम मोहम्मद में रिमांड की तारीख को शामिल करके 60/90 दिन की अवधि की गणना करने के सिद्धांत का पालन किया गया है, जैसा कि चंगंती (ऊपर) में निर्धारित किया गया है। आश्राफ्ट भट (ऊपर), प्रज्ञा सिंह

ठाकुर (ऊपर), और गौतम नवलखा (ऊपर) में।

33. एम. रवींद्रन (ऊपर) में 3-न्यायाधीशों की पीठ ने रुस्तम (ऊपर) का अनुसरण किया। a viz. रवि प्रकाश (सुप्रा), जिसमें रिमांड की तारीख को शामिल नहीं किया गया है। हालाँकि, रुस्तम (ऊपर) में निर्धारित गणना, इनक्यूरियम के अनुसार होने के कारण, हमारी राय में इस रूप में नहीं माना जा सकता है

सही कानून। इसलिए, रवींद्रन (ऊपर) में न्यायालय को चंगंती में निर्धारित गणना सिद्धांत का पालन करना चाहिए था, न कि रुस्तम में।

34. विवादित फैसले में विद्वान एकल न्यायाधीश था

रुस्तम (ऊपर) और रवि प्रकाश (ऊपर) में अनुपात के प्रति सचेत जहां न्यायालय ने सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 9 को ध्यान में रखा था और कहा था कि धारा 9 में कुछ हो सकते हैं -

प्रासंगिकता जहां संबंधित कानून सीमा की अवधि और दिनों की एक श्रृंखला या किसी अन्य अवधि में पहले के बहिष्करण को निर्धारित करता है,

तब क्रम में हो सकता है। न्यायालय ने कहा कि "सिद्धांत" तब आकर्षित होगा जब एक अवधि को एक कानून या नियम द्वारा सीमित किया जाता है, जिसकी शुरुआत और अंत दोनों होते हैं; 'से' शब्द शुरुआत को दर्शाता है, यानी उद्घाटन का दिन जिसे बाहर रखा जाना है और अंतिम दिन को 'से' शब्द के उपयोग से शामिल किया जाता है। धारा 9 के लागू होने के लिए 'से' की आवश्यकता 'और' से 'तक' की अवधि के लिए निर्धारित की गई है, यानी जब अवधि को अंतिम समय और अंतिम समय द्वारा चिह्नित किया जाता है। यह सिद्धांत है कि

सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 9 की प्रयोज्यता के लिए अंतर्निहित विधि। महत्वपूर्ण रूप से, धारा 167 आवेदन में, जांच को पूरा करने के लिए कोई प्रारंभिक या अंतिम बिंदु नहीं है। योजना में

सी. आर. पी. सी., जैसा कि ऊपर विस्तार से बताया गया है, उप [2023] 5 एस. सी. आर. में निहित प्रावधान।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 167 की धारा (1) उप-धारा (2) की निरंतरता में चलती है। मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी को पेश करना पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी की अगली कड़ी है और साथ ही, आरोपी को भी अपनी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। जिस दिन अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष रिमांड पर लाया जाता है, धारा 167 की उप-धारा (2) मजिस्ट्रेट को या तो उसे जारी रखते हुए या मजिस्ट्रेट हिरासत में भेजकर पुलिस के साथ हिरासत को अधिकृत करने का अधिकार देती है। दोनों प्रक्रियाओं के बीच विराम नहीं हो सकता है। धारा 167 में किसी भी सीमा-उन्मूलन की अवधारणा नहीं है और न ही ऐसा किया जा सकता है।

'और' से लेकर 'तक' की सीमा की अवधि में फिट किया जाए क्योंकि जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने की कोई सीमा नहीं है। द.

मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की निरंतरता में एक प्रक्रिया है और मजिस्ट्रेट पूरी तरह से 15 दिनों से अधिक के लिए हिरासत को अधिकृत नहीं करेगा, लेकिन यदि वह संतुष्ट है कि पर्याप्त आधार मौजूद हैं, तो वह पुलिस की हिरासत के अलावा 15 दिनों से अधिक समय के लिए आरोपी की हिरासत को अधिकृत कर सकता है। उल्लेखनीय है कि ऐसा कोई निश्चित अंतिम बिंदु नहीं है जिसके भीतर पुलिस या जांच अधिकारियों को जाँच पूरी करें। हालांकि, यदि जांच पूरी नहीं होती है और 60 या 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किया जाता है, तो आरोपी को डिफॉल्ट जमानत का अधिकार प्राप्त होता है। रिमांड से पहले पुलिस के साथ हिरासत की पूर्व अवधि हिरासत नहीं है। यह केवल इसलिए है, एक के अनुसार

मजिस्ट्रेट से जारी प्राधिकरण। मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत की अवधि रिमांड आदेश के दिन से चलती है। की उप-धारा (2) सी. आर. पी. सी. की धारा 167 मजिस्ट्रेट की शक्ति से संबंधित है

एक अभियुक्त को रिमांड पर लें और ऐसा कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त पर मैगिस्टेरियल कोर्ट की नज़र की तारीख को बाहर रखा जाना चाहिए। किसी अभियुक्त को लंबे समय तक कैद में रखने से बचने के लिए केवल इसलिए कि जाँच आराम से की जा रही है, विधायिका को अभियुक्त को डिफॉल्ट जमानत पर रिहा होने का अधिकार देने के लिए कहा गया था यदि वह जमानत बांड देने के लिए तैयार है और जाँच अभी भी जारी रह सकती है। यही कारण है कि सामान्य खंड अधिनियम को धारा 167 की उप-धारा (2) पर लागू नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, रिमांड आदेश की तारीख को छोड़कर आरोपी की हिरासत की निरंतरता में भी विराम होगा जो धारा 56 के तहत उसकी गिरफ्तारी की तारीख से शुरू होती है और धारा 167 के तहत निर्धारित 60/90 दिन की अवधि तक जारी रहती है। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब हम रिमांड आदेश की तारीख को निर्धारित रिमांड अवधि के पहले दिन के रूप में शामिल करते हैं-तो कोई निश्चित 60-दिन की अवधि नहीं होती है जिसके लिए आरोपी को रिमांड पर लिया जाता है। एक बार जब मजिस्ट्रेट रिमांड को अधिकृत कर देता है, दिन के समय की परवाह किए बिना, जब वह ऐसा करता है, तो अभियोजन पक्ष, प्रत्येक मामले में, भारत सरकार V.

कपिल वधावन और ए. एन. आर. ईटीसी। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

धारा 167 (2) के परंतुक ए (ii) के तहत आने वाले अपराधों के लिए हिरासत की अलग-अलग अवधि है जो 59 दिनों और 23 घंटों या 59 दिनों और 1 घंटे या उससे अधिक के स्पेक्ट्रम से चलती कर्सर तरीके से हो सकती है। एक अभियुक्त के लिए रिमांड की सटीक अवधि मैगिस्टेरियल अदालत की पहली नज़र और रिमांड आदेश पर हस्ताक्षर के अधीन है। यह चंगती (ऊपर) में इस निष्कर्ष की व्याख्या करता है कि सामान्य खंड अधिनियम धारा 167 सी. आर. पी. सी. पर लागू नहीं होता है, क्योंकि कोई निश्चित अवधि नहीं है जिससे निर्धारित रिमांड शुरू हो सकती है। इसके अलावा, यह तथ्य कि रिमांड की तारीख शामिल है और निर्धारित अवधि से बाहर नहीं है,

इस महत्वपूर्ण विचार के आधार पर कि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदेश देती है कि कानून की विशिष्टता में किसी भी कमी की व्याख्या अभियुक्त के पक्ष में की जानी चाहिए।

35. विद्वान ए. एस. जी. ने ई. सी. ओ. एन. 22 और साकेत 2,3 पर भरोसा रखते हुए तर्क दिया कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 9 लागू होगी।

धारा 167 सी. आर. पी. सी. के लिए, क्योंकि एक विशेष समय अवधि तय की गई है, चाहे 'से' और 'से' तक, जिसके भीतर जांच की जानी है। यह हमें गलत लगता है क्योंकि कोई निश्चित समय अवधि नहीं है जिसके तहत जांच पूरी की जानी है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, जब हम धारा 167 के तहत निर्धारित 60/90 दिन की अवधि में रिमांड की तारीख को शामिल करते हैं, तो इसके परिणामस्वरूप अलग-अलग रिमांड अवधि होगी जो वास्तव में कुल राशि के बराबर नहीं होगी।

एक साफ 60/90 दिन का समय। इस प्रकार, सामान्य खंड अधिनियम को लागू नहीं किया जा सकता।

36. सी. आर. पी. सी. की धारा 57 में आदेश दिया गया है कि आरोपी को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर और धारा 167 (2) के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए।

न्यायिक मजिस्ट्रेट से कार्यकारी कार्रवाई की जांच करने और यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि क्या पुलिस कार्रवाई से अभियुक्तों के अधिकार कम नहीं हुए हैं। कार्यपालिका और न्यायिक शक्ति का पृथक्करण, अंततः किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है जो

अनुच्छेद 21 और 22 (2) के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित। यदि मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित रिमांड की तारीख को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो एक आरोपी हिरासत में होने के बावजूद, उसे दिन की अवधि के भीतर नहीं गिना जाएगा। रिमांड की तारीख पर हिरासत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 56 के तहत एक आरोपी की गिरफ्तारी से अलग है क्योंकि इसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले की अवधि माना जाता है। इस तर्क के अनुसार, भले ही आरोपी हिरासत में हो, यह न तो धारा 56 के तहत होगा और न ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत। इससे एक स्पष्ट कानूनी रिक्तता पैदा होगी। हालाँकि इससे बचा जा सकता है यदि 22 इकॉन एंटी लिमिटेड बनाम रोम इंडस्ट्रीज [(2014) 11 एस. सी. सी. 769] 23 साकेत इंडिया लिमिटेड बनाम। इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड (1999) 3 एस. सी. सी. 1 [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रिमांड अवधि को रिमांड आदेश के दिन से ही माना जाता है। इसके अलावा, यदि किसी अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड पर लिया जाता है,

01.01.2023 , फिर, पुलिस, न्यायिक जांच के बाद, के लिए सशक्त है सी. आर. पी. सी. की धारा 167 के अनुसार उसी दिन से जांच शुरू की जाती है, भले ही पुलिस वास्तव में उसी दिन जांच शुरू करे। इसलिए, यदि पुलिस को रिमांड आदेश के दिन ही किसी आरोपी व्यक्ति की जांच करने का अधिकार है, तो 60/90 दिन निर्धारित अवधि,

जिसकी अवधि समाप्त हो जाती है, अभियुक्त को डिफॉल्ट जमानत का अधिकार प्राप्त होता है, उसकी गणना तार्किक रूप से उसी दिन से की जानी चाहिए। 60/90 दिन की अवधि में धारा 167 सी. आर. पी. सी. के तहत रिमांड की तारीख को नजरअंदाज करना, हमारी राय में, सुस्त जाँच के कारण एक अभियुक्त को लंबे समय तक हिरासत में रहने से सुरक्षा प्रदान करने के विधायी इरादे के खिलाफ विद्रोह करना।

37. राकेश कुमार पॉल बनाम असम राज्य 24 में तीन न्यायाधीश

वैधानिक पर विचार करके ऐसे आवेदन से निपटने की आवश्यकता है आवश्यकताएँ, अर्थात्, क्या आरोप पत्र दाखिल करने के लिए वैधानिक अवधि

24 (2017) 15 एससीसी 67

25 (2014) 9 एस. सी. सी. 457

26 (2001) 5 एससीसी 453

27 1994 (5) एस. सी. सी. 410

28 (2020) 10 एस. सी. सी. 616 प्रवर्तन निदेश, भारत सरकार v. कपिल वधावन और ए. एन. आर. ईटीसी। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

या चालान की अवधि समाप्त हो गई थी और क्या आरोपी इसके लिए तैयार है और

जमानत देता है। दूसरे शब्दों में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) प्रथम परंतुक के तहत डिफॉल्ट जमानत का दावा करने के लिए, आरोपी को जमानत प्राप्त करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं बनाना पड़ता है और न ही उसे विस्तृत जमानत आवेदन दायर करना पड़ता है। आवेदन में उन्हें केवल इतना कहना है कि चूंकि निर्धारित दिन की अवधि समाप्त हो गई है और आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है, इसलिए वह जमानत का हकदार है और आरोपी द्वारा जमानत देने की पेशकश के बाद आरोप पत्र दायर करके इस तरह के अक्षम्य अधिकार को पराजित नहीं किया जा सकता है।

39. एस. कासी बनाम राज्य (उपरोक्त) मामले में, अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2), व्यक्तिगत अधिकार के लिए सीमा अधिनियम की प्रयोज्यता पर चर्चा की। स्वतंत्रता, और अभियोजन पक्ष का आरोप पत्र दायर करने का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने वाली अदालत ने तब कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले

कोविड-19 महामारी के आलोक में सीमा आवश्यकताओं में ढील देने का निर्देश राज्य या जांच एजेंसियों को किसी भी तरह की ढील देने की अनुमति नहीं देगा। जांच अवधि की गणना करने और इस तरह अभियुक्तों को अतिरिक्त कारावास की अनुमति देने की शर्तें-उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती।

40. अस्पष्टता के मामले में दंडात्मक कानून के निर्माण में, चाहे वह वास्तविक हो या कल्पित, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) में अंतर्निहित विधायी इरादे को पूरा करने के लिए, अस्पष्टता को अभियुक्त व्यक्ति के पक्ष में हल किया जाना चाहिए क्योंकि स्वतंत्रता दांव पर है। एम. रवींद्रन (ऊपर) में यह राय व्यक्त की गई थी जिसमें निम्नलिखित का उच्चारण किया गया था:

" जब भी निर्माण में कोई अस्पष्टता होती है

दंडात्मक कानून, न्यायालयों को इस व्याख्या का समर्थन करना चाहिए जो

अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा की दिशा में झुकता है, यह देखते हुए कि

एक व्यक्ति और व्यक्ति के बीच सर्वव्यापी शक्ति असमानता राज्य "।

41. इसी तरह, राकेश पॉल (उपरोक्त) मामले में, इस अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने धारा 167 के संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया कि जहां कानून को पढ़ने पर दो विचार संभव हैं, तो वह प्रावधान जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करता है। इसे सख्ती से पढ़ना चाहिए। यह देखा गया कि चूंकि अनुच्छेद 21 अधिकार शामिल हैं, इसलिए न्यायालय को उस व्याख्या के पक्ष में झुकना चाहिए जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखती है और उसकी रक्षा करती है। 30 यह व्याख्या इस विचार से भी समर्थित है कि संवैधानिक कानून तार्किक, नैतिक और कानूनी रूप से श्रेष्ठ है।

29 सुओ मोटू रिट याचिका (सिविल) सं. 3/2020 30 राकेश कुमार पॉल बनाम। असम राज्य, (2017) 15 एस. सी. सी. (109) पैरा 72-73, (प्रति लोकुर जे.)

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वैधानिक कानून के लिए। 31 इसलिए, कोई भी वैधानिक प्रावधान, संवैधानिक कानून के अनुरूप होना चाहिए। इसके अलावा, डिफॉल्ट जमानत के अधिकार के विशिष्ट संदर्भ में, सीआरपीसी की धारा 167 (2) के पहले परंतुक के तहत, गौतम नवलखा (ऊपर) में इस अदालत ने कहा कि डिफॉल्ट जमानत का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यदि रिमांड आदेश यांत्रिक रूप से या कानून के उल्लंघन में पारित किया जाता है या जमानत की कमी के कारण पीड़ित किया जाता है।

अधिकार क्षेत्र में, बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक रिट होगा।

42. 60/90 दिन की सीमा एक वैधानिक आवश्यकता है जो अनुमति देती है।

राज्य की एजेंसियां 15 दिनों के बाद गंभीर अपराधों की जांच करेंगी

पुलिस हिरासत। यदि राज्य निर्धारित दिन अवधि के भीतर रिमांड के लिए आरोप पत्र या पूरक अनुरोध दायर करने में विफल रहता है, तो हमें व्यक्ति के अधिकारों और उन अधिकारों पर प्रतिबंध के बीच संतुलन बनाने और कानूनी समर्थन के बिना लंबे समय तक कारावास को रोकने की आवश्यकता है। उसी उदाहरण में, वैधानिक रिमांड अवधि समाप्त हो जाती है, आरोपी को डिफॉल्ट जमानत का एक अक्षम्य अधिकार प्राप्त होता है और इसे संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता निश्चित रूप से सापेक्ष और विनियमित है। पूर्ण स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जिसकी कल्पना सामाजिक परिवेश में नहीं की जा सकती है। इसलिए कानून अधिकारियों को आरोपी व्यक्तियों को हिरासत में लेने और जांच को सुविधाजनक बनाने की अनुमति देता है। हालाँकि, यह इस अदालत का कर्तव्य है कि वह लंबे समय तक कारावास को हतोत्साहित करे। इसके अलावा, डिफॉल्ट जमानत का अधिकार बाद में आरोप पत्र दाखिल करने से समाप्त नहीं होता है, और आरोपी को डिफॉल्ट जमानत का अधिकार बना रहता है।

43. संवैधानिक नींव, एक की स्वतंत्रता को छूते हुए

व्यक्ति को पहली बार ए. के. गोपालन 3 2 में न्यायमूर्ति फजल अली की असहमत राय में समझाया गया था, जहाँ उन्होंने अधिकारों की अंतःक्रियाशीलता के सिद्धांत का वर्णन किया था। आर. सी. कूपर 3 3 और मेनका गांधी के बाद के मामले में यह अल्पसंख्यक दृष्टिकोण बहुमत का फैसला बन गया। 3 4 इस सिद्धांत में कहा गया है कि

मौलिक अधिकार अलग-थलग और अलग नहीं हैं, बल्कि स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का एक परस्पर जुड़ा हुआ जाल बनाते हैं। कोई भी कानून जो छीन लेता है

संविधान। 33 रुस्तम कावासजी कूपर बनाम भारत संघ (1970) 1 एस. सी. सी. 248, पैरा-1,4 और 5 34 मेनका गांधी बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 597 पैरा 216,218 से 227 (प्रति एच. बेग जे.) , पैरा 47 और 56 (जे. चंद्रचूड़ के अनुसार)

प्रवर्तन निर्देश, भारत सरकार V. कपिल वधावन और ए. एन. आर. ईटीसी। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

धारा 167 सी. आर. पी. सी. की वैधानिक रूपरेखाओं को दी गई व्याख्या को अनिवार्य रूप से तर्कसंगतता, निष्पक्षता और अधिकारों की अपरिवर्तनीयता के मानकों तक मापना होगा। इसके अलावा, केशवानंद भारती मामले में इस अदालत ने, 35, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सीकरी के माध्यम से बोलते हुए कहा कि भारत ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) और अनुच्छेद 51 में संवैधानिक जनादेश को स्वीकार करने के बाद, न्यायालय से अधिकारों को अपरिहार्य मानने की आवश्यकता होगी, और इससे संवैधानिक व्याख्या का मार्गदर्शन होना चाहिए।

44. इस स्तर पर, हम ओल्मस्टेड बनाम में न्यायमूर्ति लुई डी. ब्रांडेस की असहमत राय को याद रखने से लाभान्वित हो सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर 1920 का फैसला एक सदी के बाद भी सही साबित हुआ। न्यायमूर्ति ब्रांडेस ने कहा:

" अनुभव को हमें सबसे अधिक सतर्क रहना सिखाना चाहिए

स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए जब सरकार के उद्देश्य हैं

लाभप्रदा। स्वतंत्रता के लिए पैदा हुए लोग स्वाभाविक रूप से दुष्ट दिमाग वाले शासकों द्वारा उनकी स्वतंत्रता पर आक्रमण को रोकने के लिए सतर्क होते हैं। सबसे महान। स्वतंत्रता के लिए खतरे पुरुषों द्वारा कपटी अतिक्रमण में छिपे हुए हैं

उत्साह, सार्थक लेकिन बिना समझ के।

45. उपरोक्त परिच्छेद को न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना ने ए. डी. एम. जबलपुर में अपनी असहमति वाली राय में अनुमोदित रूप से उद्धृत किया था। 37 इस बात पर शायद ही जोर दिया जाना चाहिए कि डिफॉल्ट जमानत का सवाल व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। ए. डी. एम. जबलपुर में न्यायमूर्ति खन्ना के अल्पमत के दृष्टिकोण को के. एस. पुट्टास्वामी, 38 में गोपनीयता निर्णय में न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की प्रमुख राय में मंजूरी मिली, जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अभाव में भी, राज्य के पास किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने की कोई शक्ति नहीं है।

कानून का अधिकार; कि आवश्यक अभिधारणा और बुनियादी धारणा है। 39 यह तार्किक रूप से इस प्रकार है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अविभाज्य हैं और ऐसे अधिकार हैं जो एक गरिमापूर्ण मानव अस्तित्व से अविभाज्य हैं। 35 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) 4 एससीसी 225। (प्रति सी. जे. सीकरी) 36 ओल्मस्टेड बनाम। यूएस, 277 यूएस 438 (1928), असहमति

38 केएस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) 10 एस. सी. सी. 1. 39 न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, के. एस. पुट्टास्वामी बनाम संघ के मामले में अपने बहुमत की राय में। भारत (2017) 10 एस. सी. सी. 1, जॉन लॉक के दूसरे ग्रंथ (1690) का हवाला देते हुए कहता है कि स्वतंत्रता मौलिक प्राकृतिक कानून का मामला है।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

46. 'प्राकृतिक स्वतंत्रता' पर लिखते हुए, विलियम ब्लैकस्टोन ने अपनी पुस्तक में

1965 में इंग्लैंड के कानूनों पर टिप्पणियों ने उन्हें पूर्ण अधिकारों के रूप में वर्णित किया जो प्रकृति के अपरिवर्तनीय कानूनों द्वारा व्यक्ति में निहित थे। दूसरे शब्दों में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को एक अपरिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय अधिकार के रूप में मान्यता दी गई।

47. व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सीधे तौर पर मानव गरिमा और व्यक्तित्व के प्रति अपरिहार्य अधिकार से संबंधित है। गरिमा की अवधारणा है

हमारे संवैधानिक कानून के विमर्श के केंद्र में। वास्तव में, प्रस्तावना स्वयं 'व्यक्ति की गरिमा' को बनाए रखने की गारंटी प्रदान करती है। संविधान योजना में यह प्रावधान है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार सहित सभी मानवाधिकार एक विशेष मौलिक के विनिर्देश हैं।

अधिकार-यह अपनी व्यक्तिगत गरिमा का सम्मान करने का अधिकार है। विद्वान हन्ना अरेंड्ट ने भी इसी प्रस्ताव का समर्थन किया है।

अरेंड्ट के अनुसार, गरिमा में अधिकार प्राप्त करने का अधिकार और किसी प्रकार की संगठित राजनीतिक सदस्यता का समान अधिकार शामिल है।

समुदाय '। 40 इसके अलावा, दुनिया भर की संवैधानिक अदालतों ने इस बात का समर्थन किया है कि मानव गरिमा और समानता का सवाल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार है। 41 मुन बनाम इलिनोइस 42 में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिकी संविधान के 14 वें संशोधन के संदर्भ में स्वतंत्रता शब्द की व्याख्या की और कहा कि "स्वतंत्रता" शब्द का अर्थ, जैसा कि प्रावधान में उपयोग किया गया है, केवल शारीरिक संयम या जेल की सीमा से मुक्ति से अधिक है। इसका अर्थ है जहाँ कोई व्यक्ति चाहे वहाँ जाने की स्वतंत्रता, और इस तरह से कार्य करने की स्वतंत्रता, जो दूसरों के समान अधिकारों के साथ असंगत न हो, अर्थात् ऐसे आह्वान और प्रस्तावों को आगे बढ़ाना जो (व्यक्तिगत) क्षमताओं को विकसित करने और उन्हें उनका उच्चतम आनंद देने के लिए सबसे उपयुक्त हो। 43 इन शब्दों को बाद में इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के संदर्भ में यह सुझाव देने के लिए अपनाया गया था कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अर्थ केवल पशु अस्तित्व नहीं है, बल्कि एक गरिमापूर्ण अस्तित्व है। 44

48. आइए अब हम विद्वान ए. एस. जी. द्वारा प्रस्तावित तर्क का परीक्षण करें, कि यदि किसी अभियुक्त को 11 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है: 50 प्रधानमंत्री ए. दिए गए दिन, मान लीजिए, 01.01.2023, और यदि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 9

4 हन्ना अरेंड्ट, अधिनायकवाद की उत्पत्ति (1951) 41 जर्मन संविधान (1945) और हेलसिंकी समझौते (1975) देखें। 42 मुन्न बी. इलिनोइस, 94 यू. एस. 113 (1876)

43 मुन्न बनाम. इलिनोइस, 94 यू. एस. 113 (1876), पृष्ठ 142। मुन्न बी. इलिनोइस-खरक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1964) 1 एस. सी. आर. 332 और बाद में के. एस. पुट्टास्वामी बनाम उल

(2017) 10 एस. सी. सी. 1 के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत।
44 फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम। प्रशासक, 1981 ए. आई. आर 746। (प्रति पी. एन. भगवती जे.)

प्रवर्तन निर्देश, भारत सरकार V. कपिल वधावन और ए. एन. आर. ईटीसी। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

59 दिनों से अधिक की अवधि, और कुछ घंटे, इस पर आधारित है अनुच्छेद 22 (2) और अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त को संवैधानिक संरक्षण दिया जाता है। इस तरह, एक अभियुक्त के साथ व्यवहार करने में संहिता का आवेदन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के अलंघनीय अधिकार के अनुरूप होगा, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

49. अब अंग्रेजी दार्शनिक जॉन लॉक की ओर लौटते हुए,

जिनके शब्दों से यह निर्णय शुरू हुआ, 45 हमने कानून की उस व्याख्या का समर्थन करके इस संदर्भ का जवाब देने के लिए चुना है जो न्याय और स्वतंत्रता के कारण को आगे बढ़ाता है। सी. आर. पी. सी. के प्रासंगिक प्रावधान कानून हैं, जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। यह गंभीर मामलों में आरोपित व्यक्तियों को सीमित हिरासत में रखने की सामाजिक आवश्यकता को नियंत्रित करता है।

अपराध। इसलिए हमने इस व्याख्या को अपनाया है जिसके द्वारा व्यक्तिगत

स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है और न्याय से समझौता नहीं किया जाएगा और चीजों की भव्य योजना में, व्यक्तियों की अन्यायपूर्ण नजरबंदी को छोड़ दिया जाता है। एक अदालत के रूप में, एक बार संहिता की कानूनी शर्तों को पूरा करने के बाद, हम कानून को लागू करने और गैरकानूनी हिरासत को रोकने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए बाध्य हैं।

50. चूंकि अनुप्रयोग और विवरण में निर्वात मौजूद है

धारा 167 सी. आर. पी. सी., हमने एक ऐसी व्याख्या का विकल्प चुना है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कारण को आगे बढ़ाती है। यहाँ अभियुक्तों को 14.05.2020 पर रिमांड पर लिया गया था और इस प्रकार, आरोप पत्र 12.07.2020 (यानी साठवें दिन) को या उससे पहले दायर किया जाना चाहिए था। लेकिन वही दायर किया गया था, केवल

45 द सेकंड ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक का तर्क है कि संप्रभुता लोगों में रहती है और प्राकृतिक अधिकारों और सामाजिक अनुबंध के संदर्भ में वैध सरकार की प्रकृति की व्याख्या करती है।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13.07.2020 जो उनकी हिरासत का 61वां दिन था। अतः अभियुक्त व्यक्तियों को 12 बजे 13.07.2020 पर व्यक्तिग्री जमानत का अधिकार प्राप्त हुआ: 00 ए. एम., आधी रात के बाद। उसी दिन, अभियुक्तों ने 8 बजे अपनी डिफॉल्ट जमानत याचिकाएं दायर कीं: 53 एएम। ईडी ने बाद में दिन में 11 बजे आरोप पत्र दायर किया: 15 एएम। इस प्रकार, डिफॉल्ट जमानत आवेदन आरोप पत्र से बहुत पहले दायर किए गए थे। रवींद्रन (ऊपर) और विक्रमजीत (ऊपर) में, जो संजय दत्त (ऊपर) में संविधान पीठ का अनुसरण करते थे, यह था

यह उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया कि यदि अभियुक्त व्यक्ति आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट दायर करने से पहले चूक जमानत के अपने अक्षम्य अधिकार का लाभ उठाते हैं, तो ऐसा अधिकार किसी भी बाद की फाइलिंग से निराश या समाप्त नहीं होगा। इसलिए हम घोषणा करते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत निर्धारित दिन की रिमांड अवधि की गणना उस तारीख से की जानी चाहिए जब मजिस्ट्रेट रिमांड को अधिकृत करता है। यदि रिमांड के पहले दिन को बाहर रखा जाता है, तो रिमांड की अवधि, जैसा कि हम देखते हैं, अनुमत 60/90 दिनों की अवधि से आगे बढ़ेगी, जिसके परिणामस्वरूप धारा 167 सीआरपीसी के तहत परिकल्पित अवधि से परे अनधिकृत हिरासत होगी। ऐसे मामलों में जहां आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट 61वें/91वें दिन या उसके बाद दायर की जाती है, हमारी सुविचारित राय में आरोपी डिफॉल्ट जमानत का हकदार होगा। दूसरे शब्दों में, जिस क्षण निर्धारित 60/90 दिन की रिमांड अवधि समाप्त हो जाती है, उसी क्षण अभियुक्त को डिफॉल्ट जमानत का एक अक्षम्य अधिकार प्राप्त हो जाता है।

51. उपरोक्त चर्चा और राय के बाद, उच्च न्यायालय का विवादित आदेश जिसमें उत्तरदाताओं को आवेदन करके डिफॉल्ट जमानत दी गई है

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) का परंतुक (ए) (ii) क्रम में पाया गया है। इसलिए, हम विद्वान द्वारा पारित दिनांकित 20.08.2020 के विवादित निर्णय को बरकरार रखते हैं।

बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश। इन अपीलों से उत्पन्न होने वाले किसी भी अन्य लंबित मुद्दे को इस न्यायालय की एक उपयुक्त पीठ द्वारा संबोधित किया जाना है।

संदर्भ

ने जवाब दिया।

निधि जैन

(सहायक: तमन्ना, एलसीआरए)